विकास के पथ पर
उत्तर प्रदेश

कानून-व्यवस्था, आधारभूत ढांचे के साथ ही विकास को लेकर सकारात्मक रणनीति के अभाव में बीमारू राज्य के रूप में पहचाना जाने वाला उत्तर प्रदेश **अब** नेतृत्व की निष्पक्ष एवं पारदर्शी नीतियों से समृद्ध प्रदेश बन रहा है।

औद्योगिक प्रदेश की राह पर यूपी

यहां अब देश व दुनिया की नामचीन कंपनियां करोड़ों का निवेश कर रही हैं और कई इसके लिए तैयार हैं। इस बदले माहौल ने उत्तर प्रदेश के उत्तम प्रदेश बनने के सपने में रंग भरने शुरू कर दिए हैं।

औद्योगिकीकरण की दिशा में उठाए गए कदमों से प्रदेश में नए रोजगार के अवसरों के सृजन और राज्य के लोगों की आर्थिक स्थिति में प्रगति की संभावनाएं साकार होती नजर आ रही हैं।

आज से साढ़े चार साल पहले की बात करें तो दिल्ली व एनसीआर में शामिल प्रदेश के गाजियाबाद, नोएडा जैसे शहरों में ही औद्योगिक इकाइयां नजर आती थीं, लेकिन ऐसा पहली बार है जब पूरे प्रदेश को ध्यान में रखकर निवेश व उद्योगों के लिए रोडमैप तैयार किया गया। प्रदेश के ज्यादातर शहरों व उससे सटे क्षेत्रों में उद्योगों की संभावनाओं के लिहाज से तैयार प्रदेश के औद्योगिकीकरण के इस खाके में जहां डिफेंस इंडस्ट्रियल कोरिडोर शामिल है तो वहीं आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्यूफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग जैसे सेक्टर शामिल हैं।

> योगी सरकार बनने के बाद राज्य में निवेश निरंतर बढ़ रहा है। रोजगार के नए अवसर खुले हैं। इसका सीधा लाभ राज्य की जनता को मिल रहा है। राज्य में कानून का राज है और सरकार भ्रष्टाचार से नहीं विकासवाद से चल रही है।
> **नरेंद्र मोदी,** प्रधानमंत्री

धरातल पर उतरते निवेश प्रस्ताव

प्रदेश में औद्योगीकरण एवं निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से फरवरी-2018 में सरकार की ओर से उप्र. इंवेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया। इसका नतीजा यह रहा कि विभिन्न सेक्टरों में 4.68 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश-प्रस्ताव मिले।

- समिट के महज 5 माह में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के प्रथम चरण में, जुलाई-2018 में 61,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश वाली 81 परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ।
- व्यावसायिक सुधारों के फलस्वरूप जुलाई 2019 में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के दूसरे चरण में लगभग 65,000 करोड़ रुपये के निवेश की 250 से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया।

हर उम्मीद पर नजर

प्रदेश में निवेश के लिए नई जमीन तैयार करने के साथ ही इसको धरातल पर उतारने की प्रक्रिया की मॉनिटरिंग भी सुनिश्चित की गई। निवेश-प्रस्तावों के अनुश्रवण के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय के अधीन ऑनलाइन एमओयू ट्रैकिंग पोर्टल तैयार कर इस पर निवेशकों, नोडल विभागों और नोडल अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी तय की गई।

218 परियोजनाओं में उत्पादन शुरू

निवेश आशयों को लेकर इस सक्रियता का यह नतीजा रहा कि करीब 1.84 लाख करोड़ रुपये के 43 प्रतिशत निवेश प्रस्ताव सक्रिय क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

- इन निवेश आशयों से करीब 1,27,000 रोजगार सृजन होगा और साथ ही 51,923 करोड़ रुपये के निवेश वाली 218 परियोजनाओं में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ हो गया है।

130 परियोजनाएं पाइपलाइन में

- 2,05,000 संभावित रोजगार के साथ 37,376 करोड़ रुपये की 130 परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं। 81.33 करोड़ रुपये निवेश की 449 परियोजनाओं को भी सरकार की ओर से आवश्यक सुविधा व सहायता प्रदान की जा चुकी है।
- 15,893 करोड़ रुपये के निवेश वाली 34 परियोजनाओं में वाणिज्यिक संचालन प्रारम्भ हो गया है, वहीं करीब 6,935 करोड़ रुपये के निवेश की 23 परियोजनाएं सक्रिय कार्यान्वयन के अधीन हैं।

मिशन रोज़गार

उप्र. डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर

5 लाख रोजगार
50 हजार करोड़ रुपये का निवेश

- भारत सरकार द्वारा अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ के प्रमुख मैन्यूफैक्चरिंग केंद्रों से होते हुए डिफेंस कॉरिडोर के विकास की घोषणा की गई।
- इस परियोजना में लगभग 5 लाख रोजगार और 50,000 करोड़ रुपये के निवेश की संभावना है।
- 5000 हेक्टेयर में प्रस्तावित इस परियोजना के लिए अधिकांश भूमि अधिग्रहीत की जा चुकी है।

फरवरी-2020 में लखनऊ में आयोजित डिफेंस एक्सपो के दौरान प्रदेश में इस सेक्टर में निवेश के लिए एमओयू हुए थे। कोविड काल के बावजूद 24 अन्य एमओयू पर भी सहमति बनी। इसके अलावा परियोजना में कई और निवेशक दिलचस्पी ले रहे हैं। बंगलूरू में आयोजित एयरो इंडिया शो-2021 के दौरान इस कॉरिडोर में निवेश के लिए 4,500 करोड़ रुपये के 13 नए प्रस्ताव मिले।

अलीगढ़ नोड में 1245 करोड़ रुपये का होगा निवेश

कॉरिडोर के अलीगढ़ नोड का उद्घाटन बीते माह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस नोड की पूरी भूमि 19 कंपनियों को आवंटित कर दी गई है। लगभग 1245 करोड़ रुपये के निवेश की उम्मीद है। यहां छोटे शस्त्रों, गोला-बारूद, एयरोस्पेस मेटल कंपोनेंट्स, एंटी ड्रोन सिस्टम, डिफेंस पैकेजिंग व अन्य उद्योगों का निर्माण प्रस्तावित है।

कानपुर व झांसी नोड में भूमि का आवंटन तीन अन्य कंपनियों को किया गया। पहली इकाई झांसी में स्थापित हो चुकी है और अन्य दो परियोजनाओं में जल्द ही कार्य शुरू हो जाएगा।

लखनऊ में तैयार होगी ब्रह्मोस मिसाइल

इस परियोजना के तहत लखनऊ नोड में ब्रह्मोस मिसाइल तैयार होगी। यहां करीब 300 करोड़ रुपये के निवेश व लगभग 5,500 तकनीकी और 10,000 गैर-तकनीकी रोजगार के अवसरों की संभावना है।

300 करोड़ रुपये का निवेश और 15 हजार से अधिक को रोजगार

इसके लिए नेक्स्ट जेनरेशन (ब्रह्मोस-एनजी) मिसाइल परियोजना को 200 एकड़ से अधिक भूमि दी जाएगी। अगस्त 2021 में डीआरडीओ के साथ इसके लिए एमओयू पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पेंट किया गया ब्रह्मोस मिसाइल का मॉडल।

इसी प्रकार झांसी में 183 हेक्टेयर में 400 करोड़ रुपये के निवेश से भारत डायनेमिक्स लि. (बीडीएल) द्वारा मिसाइल प्रोपल्शन सिस्टम की इकाई स्थापित करने के लिए एमओयू पर दस्तखत हो चुके हैं।

66,000 करोड़ रुपये का विदेशी निवेश

राज्य सरकार ने अप्रैल 2020 में स्थापित समर्पित हेल्पडेस्क के माध्यम से 96 से अधिक निवेश आशयों को आकर्षित करने में सफलता प्राप्त की। इनमें लगभग 10 देशों, जापान, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम (यूके), कनाडा, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर आदि की कंपनियों के लगभग 66,000 करोड़ रुपये के निवेश-प्रस्ताव शामिल हैं।

हीरानंदानी ग्रुप द्वारा ग्रेटर नोएडा डाटा सेंटर में 6,000 करोड़ रुपये का निवेश

अडाणी ग्रुप द्वारा नोएडा डाटा सेंटर की दो परियोजनाओं में 4,000 करोड़ रुपये का निवेश

माइक्रोसॉफ्ट द्वारा नोएडा में सॉफ्टवेयर सेक्टर में 1,800 करोड़ का निवेश

एसटीटी ग्लोबल डाटा सेंटर प्रा.लि. (सिंगापुर) द्वारा ग्रेटर नोएडा डाटा सेंटर में 900 करोड़ रुपये का निवेश

- जर्मनी की वॉन वेलेक्स का आगरा में फुटवियर विनिर्माण में 300 करोड़ रुपये का निवेश
- ग्रेटर नोएडा में दक्षिण कोरिया की सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स का 300 करोड़ रुपये का निवेश
- सैमसंग इंडिया ने 5,000 करोड़ रुपये के निवेश से नोएडा में अपना विश्व का सबसे बड़ा डिस्प्ले प्रिंट प्लांट स्थापित किया